CHETANA
International Journal of Education

Impact Factor
SJIF 2021 - 6.169

Peer Reviewed/
Refereed Journal

ISSN-Print-2231-3613
Online-2455-8729

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Received on 25th Jan. 2022, Revised on 18th Feb. 2022, Accepted 15th Mar. 2022

शोध–आलेख

झारखण्ड राज्य में बालिका आवासीय विद्यालय के प्रति समाज का अभिमत एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका : मुद्दे, चुनौतियां एवं समाधान

* कुमकुम कुमारी
शोधछात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग
**डॉ सतीश कुमार पाण्डेय
सहप्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग
राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़ झारखण्ड
Email ID: kumarikk2022@gmail.com, Mob.- 0000000000

मुख्य शब्द– बालिका शिक्षा, बालिका आवासीय विद्यालय, स्वयं सेवी संस्थाएं, झारखण्ड *आदि।*

शोध सारांश

झारखण्ड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुवा. राज्य का गठन मूल रूप से शेष बिहार के मध्य भौगोलिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर हुवा इस उम्मीद के साथ की आने वाले वर्षों में राज्य एवं राज्य के लोगों का उनके मांग के अनुरूप विकास संभव होगा. इस दिशा में स्थापना काल से राज्य के समृधि एवं विकास के लिए उतरोत्तर प्रयास हुए. जैसा की हम जानते हैं कि शिक्षा विकास का सबसे प्रभावी साधन है अतः हर वर्ग के बच्चों को कैसे निशुल्क, अनिवार्य एवं गुणात्मक शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए गंभीर प्रयास किए गए. झारखण्ड राज्य के कुल जनसँख्या में कमजोर वर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक समुदाय की जनसँख्या सबसे अधिक है और यह वर्ग ऐतिहासिक कारणों से विकास में, विशेषकर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा रहा है. शिक्षा के मामले में बालिका वर्ग जो कई कारणों से ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रह को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण कार्य है. राज्य में कमजोर वर्ग के बालिकाओं को उचित शैक्षिक वातावरण में गुणात्मक शिक्षा को पूरा करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित बालिका आवासीय विद्यालय चल रहें है. कई शोध अध्ययन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बालिका आवासीय विद्यालय की कार्यप्रभाविता में समाज का सकारात्मक सहयोग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है. प्रस्तुत आलेख

का उधेश्य झारखण्ड राज्य में बालिका आवासीय विद्यालय के प्रति समाज का अभिमत एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका, संबंधित मुद्दे चुनौतियां एवं समाधान पर एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करना है.

परिचय :

लड़कियों की शिक्षा में निवेश समुदायों, देशों और पूरी दुनिया को बदल देता है। शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की कम उम्र में शादी करने की संभावना कम होती है और स्वस्थ, उत्पादक जीवन जीने की संभावना अधिक होती है। वे अधिक आय अर्जित करते हैं, उन निर्णयों में भाग लेते हैं जो उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, और अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। लड़कियों की शिक्षा अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और असमानता को कम करती है।[1] यूनेस्को के अनुमानों के अनुसार, दुनिया भर में 129 मिलियन लड़कियां स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 32 मिलियन प्राथमिक विद्यालय की आयु और 97 मिलियन माध्यमिक विद्यालय की आयु शामिल है।[2] बालिका शिक्षा की स्थिति भारत के कुछएक राज्यों को छोड़ दें तो साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम ही है वहीं झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.41% जिसमे पुरुष साक्षरता दर 76.84% एवं महिला साक्षरता दर 53.56% है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि अभी भी झारखण्ड की कुल महिला जनसँख्या का पच्चास प्रतिशत निरक्षर है जो एक अत्यंत चिंता का विषय है I [3] बालिका शिक्षा हेतु बालिका आवासीय विद्यालय की संकल्पना भारतीय आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के क्रांतिकारी क़दमों में एक है I जिस प्रकार झारखण्ड समेत पुरे देश में महिलाएं आज भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ापन के कारण कई समस्याओं से घिरी हुई हैं बालिका शिक्षा अत्यंत आवश्यक है I जबकि प्रदेश के उन पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ बालिकाओं के लिए विद्यालीय स्तर तक की गुणात्मक शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं है बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की योजना मिल का पत्थर है। यूनेस्को के 'शिक्षा एवं लिंग समानता' संबंधी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी, भौगोलिक अलगाव, अल्पसंख्यक की स्थिति, विकलांगता, कम उम्र में शादी और गर्भावस्था, लिंग आधारित हिंसा और महिलाओं की स्थिति और भूमिका के बारे में पारंपरिक दृष्टिकोण, उन कई बाधाओं में से हैं जो महिलाओं और लड़कियों के अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने के रास्ते में आती हैं।[4] पुरे झारखण्ड समेत पुरे भारत में बालिका शिक्षा के समक्ष ये सभी चुनौतियां आज भी गंभीर सवाल खड़े कर रहें हैं I शिक्षण अधिगम की सम्पूर्ण प्रक्रिया में समाज के लोगो का नजरिया, सहयोग, सक्रीय भागीदारी का महत्वपूर्ण स्थान होता है बालिका शिक्षा हेतु किया गया कोई भी प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक की अभिभावकों का सक्रिय सहयोग सुनिश्चित न हो I इसका सकारात्मक प्रभाव शैक्षिक व्यवस्था, अधिगम एवं बच्चों के शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ता है I समाज के हर क्षेत्र में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ी है शैक्षिक योजनाओं में स्वयं सेवी संस्थाओं का सक्रीय भागीदारी भी देखा जा सकता है I झारखण्ड राज्य में सैकड़ों स्वयं सेवी संस्थाएं स्वतंत्र एवं सरकारी योजनाओं में भागीदारी निभाते हुए उसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है I किंतु बालिका आवासीय विद्यालयों के संचालन में इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण है I यह आलेख मुख्यतः अनुभवात्मक विधि द्वारा अवलोकन किए गए आंकड़ों एवं विषय के संदर्भ में उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों के सुक्ष्म विश्लेषण पर आधारित है I

झारखण्ड राज्य में बालिका आवासीय विद्यालय

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2004 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दुर्गम क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए शुरू की गई थी। यह योजना देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में लागू की जा रही है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है और साक्षरता में लिंग अंतर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए न्यूनतम 75% सीटों का आरक्षण प्रदान करती है और शेष 25% के लिए प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे के

परिवारों की लड़कियों को दी जाती है।[5] झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में जहां पर अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और जीविकोपार्जन के दशाएं विषम है, बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना एक चुनौती वाला कार्य है I यद्यपि केंद्र एवं राज्य स्तर पर इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अत्यंत पिछड़े से पिछड़े ग्रामीण इलाकों के बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का समुचित अवसर प्राप्त हो I इसी आलोक में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए 2004 में आरंभ किया गया I इसी तरह झारखंड सरकार भी झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन लगभग हर जिले में कर रही है I राज्य में झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय की संख्या 66 हैं I वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की संख्या 203 है I इन विद्यालयों की स्थापना से बालिका शिक्षा को गति एवं नई दिशा मिलने की आपार संभावनाएं है I कई समस्याओं के बावजूद आवासीय बालिका विद्यालयों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे कमजोर वर्ग के परिवारों की बालिकाओं को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है, हालाँकि राज्य में संचालित अन्य विद्यालयों की तरह ही स्थिति एक जैसी होने के कारण अभी इसे मील का पत्थर साबित होना बाकी है I

झारखण्ड राज्य में बालिका आवासीय विद्यालय के प्रति समाज का अभिमत

बालिका आवासीय विद्यालय के प्रति समाज का अभिमत कि – कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय के प्रति लोग क्या सोंचते हैं कई मायने में महत्वपूर्ण है I बालिका आवासीय विद्यालयों के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण को लेकर निरंतर शोध हुए हैं और ऐसा देखा गया है कि माता-पिता के बदलते रवैये और दी जा रही सुविधाओं के कारण बालिकाओं को पढ़ाने में अत्यधिक वरीयता दे रहे हैं और उन्हें केजीबीवी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि वे उन्हें सुरक्षित स्थान मानते हैं।[6] वर्तमान अध्ययन में स्वनिर्मित बारह प्रश्नों की एक प्रश्नावली बनाई गयी एवं रैंडम सैंपलिंग विधि से 50 अभिभावकों से इसके संदर्भ में राय जाना गया जैसा कि निचे टेबल :01 में दिया गया I इसके आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं –

बालिका आवासीय विद्यालयों के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है I अधिकांश अभिभावक इस बात की सहमती जताते है कि प्रदेश के हर प्रखंड स्तर पर बालिका आवासीय विद्यालय खुलनी चाहिए I हालाँकि मौजूदा शैक्षिक अवसंरचना एवं शिशकों की कमी के चलते अभिभावक बालिका आवासीय विद्यालयों को अन्य सरकारी विद्यालयों से बहुत बेहतर नहीं मानते हैं फिर भी बेहतर संभावनाओं के कारण भरोसा करते हैं विशेषकर सुरक्षा के मामले में I बालिका आवासीय विद्यालय की उपलब्ध अवसंरचना, सामान्य सुविधाएँ, शैक्षिक व्यवस्था, होस्टल प्रबंधन, स्वक्षता आदि के संदर्भ में अभिभावकों की प्रतिक्रिया औसत है I

टेबल संख्या : 01 बालिका आवासीय विद्यालय के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण

क्रम संख्या	प्रश्न	अभिभावकों की प्रतिक्रिया		
		हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं
1	क्या आप झारखण्ड आवासीय विद्यालय/कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के बारे में जानते हैं ?	22	18	10
2	क्या बालिका आवासीय विद्यालय प्रत्येक प्रखंड में खुलना चाहिए ?	40	02	08
3	क्या बालिका आवासीय विद्यालय बालिका शिक्षा के लिए जरुरी है ?	40	04	06
4	क्या बालिका आवासीय विद्यालय का शैक्षिक वातावरण अन्य सरकारी विद्यालयों के तुलना में अच्छी है ?	30	15	05
5	क्या क्या बालिका आवासीय विद्यालय का शिक्षण अन्य सरकारी विद्यालयों के तुलना में बेहतर है?	28	17	05
6	क्या बालिका आवासीय विद्यालय की अवसंरचना एवं सामान्य सुविधाओं से संतुष्ट हैं ?	25	25	00

7	क्या बालिका आवासीय विद्यालय से आपके बालिका की शैक्षिक स्थिति में पहले से सुधार हुई है ?	20	20	10
8	क्या बालिका आवासीय विद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावक होने के नाते भाग लेते हैं ?	20	22	08
9	क्या बालिका आवासीय विद्यालय में साफ –सफाई एवं स्वक्षता से आप संतुष्ट हैं ?	23	15	12
10	क्या आप बालिका आवासीय विद्यालय के आपातकालीन सेवाओं से संतुष्ट हैं ?	21	24	05
11	क्या आप बालिका आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक एवं प्रबंध व्ययस्था से आप संतुष्ट हैं ?	20	20	10
12	क्या आप बालिका आवासीय विद्यालय के सुरक्षा व्ययस्था से आप संतुष्ट हैं?	20	20	10

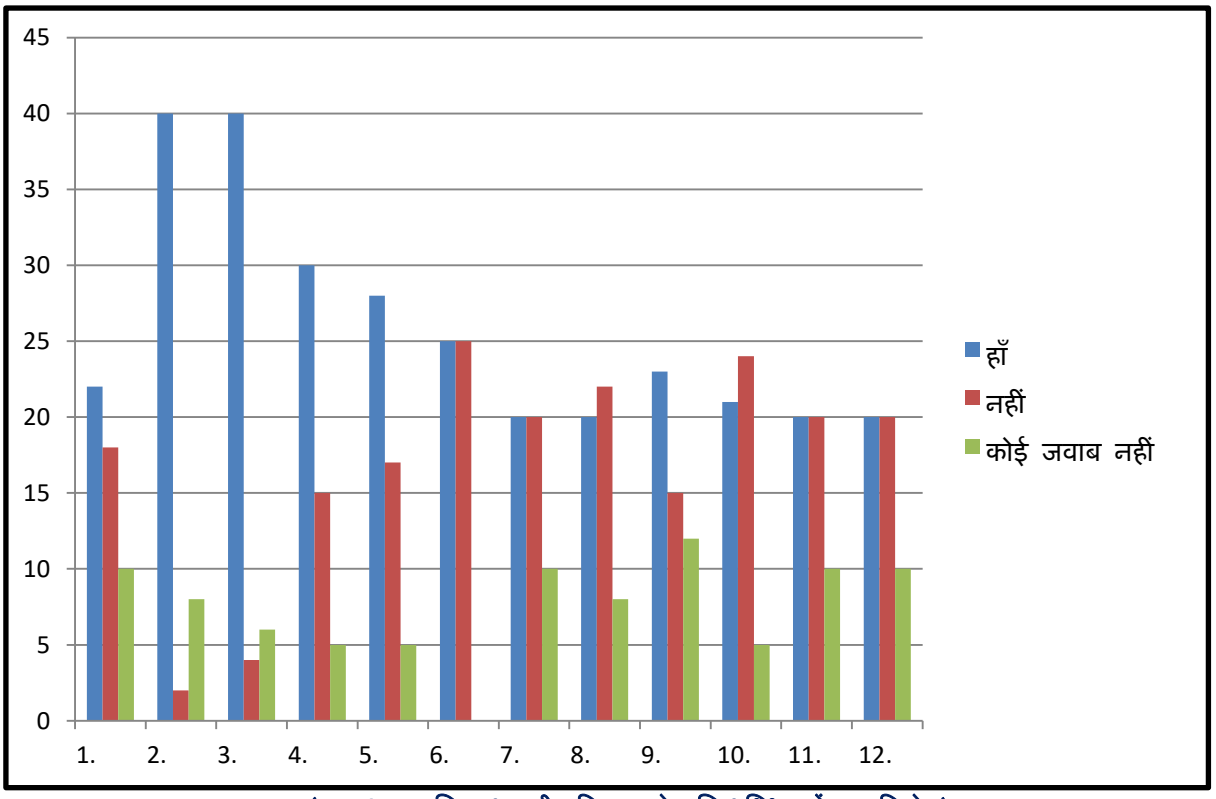

(ग्राफ 01 - बालिका आवासीय विद्यालय के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण)

झारखण्ड राज्य में बालिका आवासीय विद्यालय में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका:

झारखण्ड राज्य में मुख्य रूप से बालिका शिक्षा हेतु दो आवासीय विद्यालय संचालित हो रहें हैं – कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइड-लाइन्स के अनुसार प्रत्येक जनपद में एक समिति इन विद्यालयों की संचालन व्यवस्था की जिम्मेदार होगी, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। जिले के मुख्य विकास अधिकारी इस समिति के उपाध्यक्ष तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्ंथान के प्राचार्य इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इनके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, राजकीय बालिका इन्टर कालेज की प्रधानाचार्या, जिला बालिका शिक्षा समन्वयक के अलावा जिलाधिकारी द्वारा नामित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक (महिला को प्राथमिकता), **दो स्वयंसेवी सस्ंथाएं** तथा महिला समाख्या प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। यह

समिति जिले में स्वीकृत के.जी.बी.वी. का स्वयं अथवा किसी ऐसे **स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से संचालन** कर सकती है, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि का स्तर प्राप्त हो। इन विद्यालयों से सम्बन्धित भूमि, भवन व उपकरण राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेंगे जबकि स्वयंसेवी संस्थाएं (यदि उन्हें अधिकृत किया जाता है तो) स्वयं संचालन प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार रहेगी ।[7] झारखण्ड राज्य में सैंकड़ों स्वयं सेवी संस्थाएं हैं जो शिक्षा, साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, सेल्फ डिफेन्स,स्व रोजगार आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं सरकार के साथ पार्टनरशिप में अपनी भूमिका निभा रही है। CEDEPA-INDIA (सेंटर फॉर कैटलायज़िंग चेंज) इसी प्रकार का एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है जो झारखण्ड सरकार के शिक्षा से जुड़ी कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है । [8]

झारखण्ड में बालिका आवासीय विद्यालयों के संचालन एवं प्रबंधन में स्थापना काल से ही सक्रीय भूमिका निभातें रहें हैं । शिक्षण अधिगम के संसाधनों की व्यवस्था,शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन, स्वास्थ जाँच के लिए समय –समय पर कैंप लगाना, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेल्फ डिफेन्स का प्रशिक्षण, रोजगार कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण, होस्टल के संचालन एवं प्रबंधन में योगदान आदि कई ऐसे काम हैं जो राज्य सरकार के बालिका शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों, स्कूल एजुकेशन समेत बालिका आवसीय विद्यालयों के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं । [9]

सामाजिक भागीदारी एवं स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े मुद्दे, चुनौतियां एवं समाधान :

झारखण्ड में बालिका आवासीय विद्यालयों में विशेषकर समाज के सक्रीय भागीदारी एवं स्वयं सेवी संगठनों भूमिका से जुड़े कई मुद्दे व चुनौतियां है । इन विद्यालयों में पढने वाले विद्यार्थी मुख्यरूप से समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं जिनके माता –पिता के पास कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, कम आय, कमजोर सामाजिक प्रस्थिति, अशिक्षा, गरीबी जैसे गंभीर समस्याओं के कारण कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय के प्रभावी संचालन में सक्रीय भूमिका नहीं निभा पाते हैं । जबकि अभिभावक, सामाजिक संगठनों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय की कमी के कारण भी इन विद्यालयों की प्रभाविता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है । [10]

इसी प्रकार स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे एवं चुनौतियां भी हैं जो झारखण्ड राज्य के बालिका आवासीय विद्यालयों के प्रकार्य/क्रियाकलापों को प्रभावित करती है जैसे – स्वयं सेवी संगठनों का वितीय आवंटन की समस्याएं , विभागीय समन्वय की कमी, विद्यालय प्रबंधन के साथ समन्वय में कमी, स्वयं सेवी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि ।[11]

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों एवं झारखण्ड आवासीय विद्यालयों में समाज की सक्रीय भागीदारी एवं स्वयं सेवी संगठनों का विद्यालय के संचालन एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता है ऐसे में इससे जुड़ी मुद्दों एवं चुनौतियों का समाधान जरुरी है तभी कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय का सपना साकार हो पाएगा । इसके लिए उन कल्याणकारी योजनाओं जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षिक रूप से मजबूत एवं सामाजिक ,आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाया जा सके को ईमानदारी से लागु किया जाना चाहिए । वहीं विभिन्न सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों के निरंतर आयोजन से अभिभावकों को विद्यालय में सक्रीय सहयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए । भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को गंभीरता से निपटना जरुरी है वहीं भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ प्रयवेक्षण आवश्यक होगा ।[12]

निष्कर्ष

डॉ अम्बेडकर कहते थे कि किसी देश के विकास को समझने का बेहतर तरीका उस देश की महिलाओं की शिक्षा के स्तर की माप है ।[13]वस्तुतः यह बात एक वास्तविकता है और कोई भी देश महिलाओं की शिक्षा को अनदेखी कर एक खुशहाल एवं विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता । चुकी झरखंड जैसे पिछड़े राज्यों में जहाँ अधिकांश जनसँख्या कमजोर वर्ग के श्रेणी में आती है । जहाँ अधिकांश जनसँख्या गावों

में रहती है और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से निचे है बालिका आवसीय विद्यालयों का खुलना बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है जिसके आने वाले समय में प्रभावशाली परिणाम देखने को मिलेंगे I चुकी बालिका आवासीय विद्यालय अभी भी स्थापना के प्रारंभिक चरण में हैं तो समस्याएं एवं चुनौतियां भी कई है पर इन विद्यालयों के संचालन एवं प्रबंधन में स्थायित्व कैसे आए इस पर गंभीरता से विचार कर जरुरी कदम उठाने की आवश्यकता है.

संदर्भ ग्रन्थ सूचि

1. UNICEF Girls' education Gender equality in education benefits every child https://www.unicef.org/education/girls-education, Retrieved on 07.04.22
2. The World Bank (Feb 10, 2022). Girl's Education, https://www.worldbank.org/en/topic/girlseducation, Retrieved on 07.04.22
3. Census of India 2011
4. UNESCO https://en.unesco.org/themes/education-and-gender-equality#:~:text=The%20Education%202030%20agenda%20recognizes,equally%20in%20and%20through%20education'. Retrieved on 07.04.22
5. NITI AAYOG, Programme Evaluation Organisation Government of India(2015) Evaluation Study on Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV).
6. Seshu, A.R. (Feb 13, 2019), Khammam: Parents feel KGBVs safe place for girls, Editorial, DECCAN CHRONICLE.
7. कुमार, मयंक एवं कुमार,दिनेश (2018). बालिकाओं के शिक्षा में कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय के प्रभावों का आकलन, पी.एच. डी शोधग्रन्थ, शोध संक्षिप्तिका,Pp-01-02, http://hdl.handle.net/10603/202926, Retrieved on 07.04.22
8. **https://www.c3india.org/our_program?page=girls_education,** Retrieved on 07.04.22
9. कुमार, रामचन्द्र (2017) भारत में समावेशी शिक्षाः वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं समाधान, **विक्टोरियस पब्लिशर्स दिल्ली ,**पृष्ठ संख्या.158-164
10. कुमार, रामचंद्र (2017). इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ़ पावर्टी इनेकुँलिटी एंड एक्सक्लूशन **विक्टोरियस पब्लिशर्स दिल्ली ,पृष्ठ संख्या**.120-125
11. **वही पृष्ठ संख्या**.120-125
12. **वही पृष्ठ संख्या**.120-125
13. एक्का महेंद्र (2019) .महिला सशक्तिकरण एतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं आंबेडकर का योगदानरामचंद्र कुमार एवं माला मेश्राम , (संपादित), **२१ वीं शदी का भारत एवं डॉ भीम राव आम्बेडकर की प्रासंगिकता में ,विक्टोरियस पब्लिशर्स दिल्ली ,**पृष्ठ संख्या 54-64

***Corresponding Author**

कुमकुम कुमारी

शोधछात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग

***डॉ सतीश कुमार पाण्डेय**

सहप्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग

राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़ झारखण्ड

Email ID: kumarikk2022@gmail.com, Mob.- 0000000000